administrative and management functions in higher education; and

(c) if so, the steps being taken to achieve this?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): UGC has identified 45 Academic Staff Colleges (ASCs) in various universities for organising orientation/refresher courses for university and college teachers. In addition, 71 Departments have been selected to conduct refresher courses for in-service teachers in the university system. National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA) conducts training programmes for college Principals. A scheme for training of university and college administrators is under formulation.

Unmanned rail level crossings in Madhya Pradesh

3951. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of unmanned rail level crossings in Madhya Pradesh as on date;

(b) the details of accidents at these crossings during the last three years indicating the lives lost and persons injured therein; and

(c) remedial measures Government propose to take to prevent accidents at these level crossings in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Total number of unmanned level crossings in Madhya Pradesh is 1810.

(b) Statistics of train accidents are maintained Railway zone-wise and not State-wise.

(c) Safety measures such as rumble strips or Speed breakers and warning signs are already installed.

Railways also conduct publicity campaigns through the media to educate the public about the safety requirements at level crossings, particularly at unmanned level crossings and hazards of not following such safety procedures.

Educative campaigns conducted through mass media including Doordarshan and Radio, targetted at road users on precautions to be taken at level crossings.

Joint ambush checks are conducted in coordination with State Govts, to enforce provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and to nab errant road vehicle drivers.

Zonal Railways have also been directed to involve village Panchayats in the public awareness programme in rural and semi-urban areas.

Village level cmapaigns have been done. Short skits have been developed and played in villages to bring about awareness.

The solution lies in the road users' observing the necessary precautions. State Govt, can help by exercising strict checks while issuing driving licences, especially to drivers of trucks, buses and other heavy traffic vehicles.

दुग्ध की मांग तथा उत्पादन

3952. श्री अनंतराव देवशंकर देवः क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दुग्ध की मांग तथा उत्पादन का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दुग्ध की गुजरात सहित राज्यवार अति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है;

(ग) क्या सरकार ने दुग्ध की उपलब्धता तथा उसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु गुजरात सहित सभी राज्यों में सहकारी दुग्ध उत्पादन संघों को स्थापित करने पर विचार किया है और क्या उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) दूध की आवश्यकता तथा उत्पादन संबंधी जानकारी विवरण-I में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(ख) जानकारी विवरण-II में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अधीन, जो 31.12.1995 को बंद हो चुका है, विभिन्न राज्यों में दिनांक 31.3.1996 तक संगठित ग्राम स्तर की डेयरी सहकारी समितियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण, विवरण-III के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)। केन्द्र सरकार अब गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत, डेयरी सहकारी समितियों को संगठित करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। परियोजना के अधीन संगठित/पुनर्गठित की जा रही समितियों की राज्यवार संख्या विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

दूध की राज्यवार आवश्यकता तथा उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूध की आवश्यकता ('000 मी॰ टन/वर्ष)			दूध का उत्पादन ('000 मी॰ टन/वर्ष)		
	1993-94 (अनन्तिम)	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (प्रत्याशित)	1993-94 (अनन्तिम)	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (प्रत्याशित)
आंध्र प्रदेश	5592	5687	5782	3766	4221	4250
अरुणाचल प्रदेश	74	76	78	21	22	23
असम	1905	1946	1986	675	699	855
बिहार	7343	7502	7660	3215	3250	3500
गोवा	99	101	103	33	33	34
गुजरात	3476	3537	3598	3935	3650	3750
हरियाणा	1400	1429	1458	3850	4062	4100
हिमाचल प्रदेश	436	444	453	654	655	676
जम्मू तथा कश्मीर	657	672	687	780	780	810
कर्नाटक	3761	3817	3872	2736	3003	3260
केरल	2423	2457	2490	2001	2118	2246
मध्य प्रदेश	5601	5711	5820	4975	5160	5270
महाराष्ट्र	6668	6799	6931	4250	4811	5150
मणिपुर	157	160	164	84	111	125
मेघालय	151	155	158	53	54	60
मिजोरम	60	62	64	9	14	16
नागालैण्ड	105	109	112	45	45	45
उड़ीसा	2667	2715	2764	565	585	620
पंजाब	1693	1716	1741	5970	6215	6700
राजस्थान	3736	3813	3890	4958	4850	5200
सिक्किम	35	37	38	30	32	35
तमिल नाडु	4603	4648	4691	3524	3694	3831
त्रिपुरा	235	240	246	35	38	39
उत्तर प्रदेश	11699	11903	12105	10991	11321	11900
पश्चिम बंगाल	5715	5812	5907	3095	3240	3500
अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह	25	26	27	25	25	26
चण्डीगढ़	58	60	63	38	39	41
दादर व नगर हवेली	12	12	13	7	4	4
दमन एवं दीव	9	9	9	1	1	

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूध की आवश्यकता ('000 मी. टन/वर्ष) 1993-94 (अनन्तिम)	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (प्रत्याशित)	दूध का उत्पादन ('000 मी. टन/वर्ष) 1993-94 (अनन्तिम)	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (प्रत्याशित)
दिल्ली	828	858	888	251	257	277
लक्षद्वीप	4	4	5	1	1	1
पाण्डिचेरी	68	70	71	32	31	29
कुल:	71295	72587	73874	60605	63021	66374

टिप्पणी: दूध की आवश्यकता भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुशंसित 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के पोषणिक मानकों पर आधारित है।

विवरण-II

राज्यवार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन) 1993-94 (अनन्तिम)	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (प्रत्याशित)
आंध्र प्रदेश	148	163	162
अरुणाचल प्रदेश	62	64	65
असम	78	79	95
बिहार	96	95	101
गोवा	74	72	73
गुजरात	249	227	229
हरियाणा	605	625	618
हिमाचल प्रदेश	330	324	329
जम्मू और कश्मीर	261	256	259
कर्नाटक	160	173	185
केरल	182	190	198
मध्य प्रदेश	195	199	199
महाराष्ट्र	140	156	163
मणिपुर	118	152	168
मेघालय	77	77	83
मिजोरम	35	50	55
नागालैण्ड	94	91	88
उड़ीसा	47	47	49
पंजाब	776	797	847
राजस्थान	292	280	294
सिक्किम	186	192	204
तमिल नाडु	168	175	180
त्रिपुरा	33	35	35
उत्तर प्रदेश	207	209	216
पश्चिम बंगाल	119	123	130
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	223	215	215
चण्डीगढ़	145	142	143
दादरा एवं नगर हवेली	129	72	70
दमन एवं दीव	26	25	25
दिल्ली	67	66	69
लक्षद्वीप	50	53	54
पाण्डिचेरी	103	98	90
कुल:	188	191	197

विवरण-III

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में आपरेशन फ्लड के अंतर्गत संगठित डेयरी सहकारी समितियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समिति (संख्या)
1.	अंडमान निकोबार	सूचित नहीं किया
2.	आन्ध्र प्रदेश	5311
3.	असम	122
4.	बिहार	2722
5.	दिल्ली	—
6.	गोवा	155
7	गुजरात	11430
8.	हरियाणा	2296
9.	हिमाचल प्रदेश	178
10.	जम्मू और कश्मीर	सूचित नहीं किया
11.	कर्नाटक	7193
12.	केरल	1415
13.	मध्य प्रदेश	4215
14.	महाराष्ट्र	5807
16.	मणिपुर	सूचित नहीं किया

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समिति (संख्या)
16.	मिजोरम	सूचित नहीं किया
17.	नागालैण्ड	22
18.	उड़ीसा	1060
19.	पाण्डिचेरी	81
20.	पंजाब	6009
21.	राजस्थान	5128
22.	सिक्किम	122
23.	तमिल नाडु	8158
24.	त्रिपुरा	80
25.	उत्तर प्रदेश	9845
26.	पश्चिम बंगाल	1395
	कुल:	72744

विवरण-IV

गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं में संगठित/पुनर्गठित की जा रही डेयरी सहकारी समितियों की संख्या।

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समितियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	180
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	50
4.	असम	414
5.	बिहार	900
6.	गुजरात	240
7.	हरियाणा	75
8.	जम्मू और कश्मीर	517
9.	मध्य प्रदेश	516
10.	महाराष्ट्र	714
11.	मणिपुर	60
12.	मेघालय	36
13.	मिजोरम	46
14.	नागालैण्ड	80
15.	उड़ीसा	375
16.	सिक्किम	155
17.	तमिल नाडु	489
18.	त्रिपुरा	13[illegible]
19.	उत्तर प्रदेश	1000
20.	पश्चिम बंगाल	240
	कुल:	6232

सिंचित तथा असिंचित भूमि के क्षेत्रफल में अन्तर

3953. श्री राम जेठमलानी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचित भूमि तथा असिंचित भूमि के क्षेत्रफल तथा उसमें होने वाले औसत उत्पादन में भारी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में देश में सिंचित तथा असिंचित भूमि का पृथक-पृथक कितना-कितना क्षेत्रफल उपलब्ध था और उनकी उत्पादन क्षमता क्या-क्या थी तथा दोनों प्रकार की भूमि के उत्पादन में कितने प्रतिशत अंतर आंका गया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के भू-उपयोग आंकड़ों (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, देश में निवल बोए गए 142.51 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में से 50.10 मिलियन हैक्टेयर भूमि सिंचित थी तथा 92.41 मिलियन हैक्टेयर भूमि असिंचित। देश में 1995-96 में सिंचित भूमि के 52 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था जो देश में बोए जाने वाले कुल निवल क्षेत्र का लगभग 36.5 प्रतिशत है।

सिंचित और असिंचित भूमि में होने वाली औसत उपज में जो अंतर होता है वह फसलों और क्षेत्र की भिन्नता के कारण होता है। असिंचित भूमि में होने वाली उपज की तुलना में सिंचित भूमि में होने वाली उपज औसतन 70 से 120 प्रतिशत तक अधिक है।

Loss due to inefficient utilisation of wagon

3954. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what was the estimated loss to the Railways, zone-wise, during the last three years, year-wise, due to wasteful haulage and inefficient utilisation of wagon capacity and non-generation of earning capacity;

(b) what suggestions were given by the CAG and other consultative and advisory